[illegible]

[illegible]

लेखक

दत्तोपंत ठेंगडी

अनुवादक

[illegible] जोशी

अर्चना प्रकाशन

भावी पीढ़ियों की चेतावनी

सांख्य-वाहिनी समाप्त करो

लेखक

दत्तोपंत ठेंगड़ी

अनुवादक

मनोज जोशी

अर्चना प्रकाशन

वरिष्ठ चिंतक और विचारक माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तिका "Posterity Warns - Scrap Sankhya Vahini" का हिन्दी अनुवाद "भावी पीढियों की चेतावनी सांख्य वाहनी समाप्त करो" प्रकाशन करते हुए हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं यह पुस्तिका अभी तक अंग्रेजी में उपलब्ध थी । विषय की गंभीरता और प्रासंगिकता के कारण इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाना आवश्यक है । पुस्तक का हिंदी में प्रकाशन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उठाया एक कदम है ।

देश आर्थिक उपनिवेशवाद की कठिन चुनौती से जूझ रहा है । हमारी सप्रभुता नष्ट करने के प्रयास निरंतर जारी हैं । भारत सरकार की प्रस्तावित योजना सांख्य वाहिनी इसी कड़ी का एक हिस्सा है । जिसके माध्यम से अमेरिकी कम्पनी आई.यू.नेट का भारतीय संचार व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाएगा । इस योजना में भारत सरकार के मंत्रालयों की हिस्सेदारी भी है, लेकिन नकेल आई.यू.नेट के हाथों में रहेगी । सांख्य वाहिनी देश के डाटा नेटवर्क का केन्द्र, इंटरनेट की रीढ़ और एक प्रकार से संचार व्यवस्था का आधार होगी ।

प्रस्तुत पुरतक मे साख्य वाहिनी गठित करने के लिए हुये समझौतों और योजना को मंजूरी देने के पीछे दिये सच को उजागर किया है । साथ ही इस योजना के दुष्परिणामों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है ।

पुस्तक के हिंदी अनुवाद का महत्वपूर्ण दायित्व श्री मनोज जोशी ने निभाया है । डा. राममूर्ति गोयल, सहित अन्य सभी जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं । आशा है पुस्तक अपने उद्देश्य में सफल होगी ।

प्रकाशक

सांख्य वाहिनी एक रहस्यमयी खतरनाक पहेली

लोग साख्य वाहिनी के बारे में गुपचुप तौर पर बात करते हैं । मीडिया भी इसके बारे में चुप है । उच्च शासकीय अधिकारियों से बात कीजिए वे एक गहराई में डूब जाते है । वे कहते हैं "हमे ऊपर से आदेश है, कि हम इसके बारे में न तो कुछ बात करें और न ही कोई रहस्य खोलें ।" जैसा कि होता है राजनीतिज्ञ बहाने बनाते हैं । पूर्ण पारदर्शिता कहां चली गयी?

वास्तव में यह एक रहस्यात्मक पहेली है । क्या मीडिया को भी इस बारे में साध लिया गया है? सांख्य वाहिनी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बहुत कम अधिकारी सम्बद्ध थे । ये अधिकारी समय-समय पर दो पेराग्राफ की एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी करते रहे जिसमें हर बार लगभग एक ही बात लिखी होती थी कि यह कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग (अमेरिका) की सहयोगी कम्पनी आई. यू. नेट (IUNET) और प्रसारण सेवा विभाग (TDS) का संयुक्त उद्यम है । उनका कहना है कि यह भारत के लिए अंतर-विश्वविद्यालयीन डाटा नेटवर्क बनेगा ।

3000 करोड़ रू. की इस परियोजना के साथ जो गोपनीयता बरती जा रही है वह चक्कर में डालती है । इसे षड्यन्त्रकारी गति से क्रियान्वित किया जा रहा है । सरसरी तौर पर अध्ययन करने पर ही मालूम होता है कि यह सभी आर्थिक तर्कों और कूटनीतियों का उल्लंघन करता है । यह कार्य किसी ऐसी लॉबी के दबाव में किया जा रहा है, जिसके आका इस देश के बाहर के हो सकते हैं । इस बात पर विश्वास करने का एक महत्वपूर्ण कारण है ।

'सांख्य वाहिनी' इस देश के साथ एक धोखा है । वित्तीय दृष्टि से यह "सेल आऊट" है । यह भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, भारतीय वायरलेस एक्ट 1933 और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 और नई दूरसंचार नीति 1999 का उल्लंघन है । सांख्य वाहिनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है । फिर भी इसे रक्षा मंत्रालय या उच्च वैज्ञानिकों से एक बार भी सलाह लिए बिना अंतिम रूप दे दिया गया । यह जासूसी, कूटनीतिक संदेशों, वैज्ञानिक डाटा, टेलीफोन वार्ताओं, फेक्स और ई-मेल को एक विदेशी शक्ति द्वारा

पकड़ने के दरवाजे खोलता है । यह भारत सरकार, संस्थाओं तथा व्यापार और कुल मिलाकर जीवन के सभी अंगों के साथ एक अपरिवर्तनीय समझौता है ।

किन्तु दु:खद तथ्य यह है कि 19 जनवरी 2000 को केन्द्रीय मंत्री-परिषद ने इस खतरनाक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उससे मालूम पड़ता है कि इसे एक राष्ट्रीय मिशन के रूप मे लिया जा रहा है । उसके तुरन्त क्रियान्वयन हेतु सभी नियमों व कानूनों को हटा कर आवश्यक सामानों के मुक्त आयात की अनुमति दी गयी है ताकि यह परियोजना 9 माह में पूरी हो सके । ऐसी सूचना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीप 1000 एकड़ जमीन सांख्य वाहिनी के मुख्य कार्यालय हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है ।

यह सचमुच अचंभित करने वाला है । यह अपने तरह का पहला उपक्रम है । एक संवेदनशील शासकीय विभाग आई.यू.नेट इंक. जैसी अनजान संस्था के साथ एक संयुक्त कम्पनी खोलने के लिए हाथ मिला रहा है । इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि यह किसी अन्य संस्था जिसकी पहचान छुपाई जा रही है का दूसरा चेहरा है । हमारी जांच से पता चलता है कि आई.यू.नेट "कम्पनी" शब्द की परिभाषा को पूरा नहीं करती । अधिक से अधिक यह एक सेवा संस्था है । इस परियोजना ने दूरसंचार विभाग और सूचना तकनीक मंत्रालय में भी भौंहे चढ़ा दी हैं ।

केबीनेट द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी के तुरन्त पश्चात दूरसंचार विभाग के सचिव को हटा कर एक लचीले रुख वाले अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है । ऐसा कहा जाता है कि पूर्व सचिव अनेक आपत्तियाँ उठा रहे थे । हालांकि अमेरिकी संस्था के साथ डाटा नेटवर्क बनाने के समझौता पत्र (MOU) पर इन्ही सचिव महोदय द्वारा दिनांक 2 नवम्बर को हस्ताक्षर किए गए थे । तकनीकी एवं व्यापारिक परियोजना के नाम से सांख्य वाहिनी पर अंतिम परियोजना रिपोर्ट अमेरिका की एक कूटनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक सलाहकार सेवा संस्था द्वारा जनवरी 1999 में तैयार की गयी थी । यह रिपोर्ट जो कि एक गोपनीय दस्तावेज है, से मालूम पड़ता है कि सांख्य वाहिनी बहुत जल्दी भारत के राष्ट्रीय इन्टरनेट की रीढ़ बन जाएगी । यह विदेश संचार निगम लिमिटेड (विसनिलि) जो कि वर्तमान में भारत के इन्टरनेट की रीढ़ है, को तोड़-फोड़ कर

वास्तविक रूप से उसे हटा देगा । पुन: यह राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 का भी उल्लंघन करता है जिसमें वादा किया गया था।

'भारत में उत्पन्न या समाप्त होने वाले सभी संदेश विसनिलि के गेटवे से गुजरना चाहिए अथवा यदि यह संदेश विसनिलि के गेटवे से नहीं गुजरते है तब भी इन्हें भारतीय गेटवे पर नियंत्रित करना सम्भव होना चाहिए । यदि इस प्रकार के संदेश विसनिलि के गेटवे से नहीं गुजरते हैं तो विसनिलि को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ।'

सांख्य वाहिनी में ऐसी कोई गारन्टी नहीं दी गयी है । यहाँ आईयूनेट कों पूर्ण तथा अन्तिम प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है ।

हमारी जांच से पता चला है कि दूरसंचार विभाग के अनेकों अधिकारियों ने इस परियोजना के कूटनीतिक एवं वित्तीय निहितार्थों के सम्बन्ध में गम्भीर आपत्तियाँ एवं शंकाएँ उठाई थी । किन्तु इन्हें खारिज कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि यह प्रस्ताव लगभग एक साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया । मूलत: इसे सितम्बर 1999 मे कार्यान्वित होना था ।

अब इसे जनवरी 2000 में पुनर्जीवित किया गया है अनेक इस बात पर विश्वास करते हैं कि इसे मार्च मे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा को ध्यान में रख कर किया गया है ।

वे संदिग्ध संस्थाएँ हैं :

इस परियोजना के विस्तार में जाने से पहले इसमें लगे हुए व्यक्तियों की निष्ठा और संयुक्त उपक्रम की सहयोगी आई. यू. नेट के वास्तविक तकनीकी ज्ञान की जाँच कर लें ।

आई.यू.नेट के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि यह इस क्षेत्र में ख्याति का कोई विशेष दावा नहीं कर सकती । अनेक विशेषज्ञों ने तो इस कम्पनी का नाम तक नहीं सुना है । अनेक इस बात पर विश्वास करते है कि यह केवल एक कागजी कम्पनी है । किसी भी प्रकार से यह जानकारी नहीं मिलती कि इस कम्पनी ने विश्व में कही भी इस प्रकार की परियोजना का कार्य किया हो । सूचना प्रौद्योगिकी एवं साफ्टवेयर विकास के राष्ट्रीय टॉस्कफोर्स की प्रारम्भिक रिपोर्ट में भी यह बात कही गयी है ।

अमेरिका के पिट्सबर्ग के अग्रणी शैक्षणिक संस्थान कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय द्वारा आई.यू. नेट की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गति डाटा नेटवर्क स्थापित कर उच्च तकनीक इंटरनेट की रूपरेखा बनाने उसका विकास करने तथा प्रबंध करने मे रीढ़ की भूमिका निभाना है । इस इंटरनेट रीढ़ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करना है । इनके प्रोग्राम मे अमेरिका तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाओं की शैक्षणिक सामग्री रहेगी । यह विश्व के सभी इन्टरनेट - उपयोगकर्ताओं लिए किसी भी स्थान, किसी भी समय उपलब्ध कराएगा ।

आई. यू. नेट ईंक. अमेरिकी प्रोद्यौगिकी निगमों (अग्रणी प्रोद्यौगिकी संस्थाओं) की भागीदारी में भारत मे एक उपक्रम लगाएगा जो आई.यू.नेट (इंडिया) के नाम से जाना जाएगा । आई.यू.नेट (इंडिया) दूरसंचार विभाग, उसके निगमों तथा अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं की सूची में इंडियन इंस्टीयूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी, (। । T) हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांईस (।IS), बैंगलोर और सभी छह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी (।।T) होंगे । आधुनिक नेटवर्किंग सुविधाओं के विकास, विस्तार तथा उपयोग हेतु भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं की वचनबद्धता को निश्चित, वास्तविक तथा निरन्तर बनाए रखने के लिए उनकी भागीदारी आवश्यक है ।

आई.यू.नेट (इंडिया), दूरसंचार विभाग एवं महत्वपूर्ण प्रोद्यौगिकी हस्तांतरणकर्ता इस राष्ट्रीय रीढ़ के निर्माण को संयुक्त रूप से समन्वित करेंगे । इसके लिए मौजूदा डार्क फाइबर को लाईट करने, नए आधुनिक फाईबरों के बण्डल बिछाने मौजूद फाइबरो की क्षमता को चौड़ी बैण्ड तक बढ़ाने तथा कुछ फाइबरों को केवल इस रीढ़ के लिए मल्टीपलेक्स तथा एग्रीमेंट करना आवश्यक होगा । इस नेटवर्क के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी आई.यू.नेट (इंडिया) आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण करेगा ।

तकनीकी तथा व्यवसायिक योजना बनाने के लिए दूरसंचार विभाग तथा प्रत्येक शैक्षणिक संस्था से दो व्यक्तियों के नामांकन का प्रावधान है, जो आई.यू. नेट ईंक. के साथ कार्य करेंगे । आवश्यक होने पर आई. यू.नेट व्यावसायिक योजना की रूपरेखा बनाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु व्यावसायिक सलाहकार संस्थाओं को सम्बद्ध करेगा।

दूसरी बात यह कि वे किसी प्रकार के भारत में विदेशी निवेश का वादा नहीं कर रहे हैं । जो कुछ भी वो ला रहे है वो है - 'केवल ज्ञान (Know How) मात्र इसके लिए उन्होंने कम्पनी के कुल इक्वीटी के 49 प्रतिशत भाग का अधिकार प्राप्त कर लिया है । क्या यह उचित है? वास्तव में उनकी इतनी बड़ी भागीदारी उन्हें पहले पाँच साल के लिए इस परियोजना को अपने अनुसार नियंत्रित करने की योग्यता प्रदान करेगी ।

उनके दो साहसी सम्पर्क अधिकारी हैं । और वे दो कौन हैं? एक है डॉ. राज रेड्डी, हेबोर्ट साईमन प्राध्यापक और हाल तक स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साईंसेंस कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय के डीन । अब वे भारत मे आई.यू.नेट का प्रतिनिधित्व करते हैं । श्रीमान बिल क्लिंटन को कूटनीतिक मुद्दों पर सलाह देने वाली पेनल के भी डॉ. रेड्डी सदस्य थे । दूसरे सज्जन हैं डॉ. वी. एस. अरूणाचलम् । अस्सी के दशक के पूर्वाद्ध मे जब वे भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण उन्होंने भारत छोड़ा और अमेरिका में बस गए । वर्तमान में वे यांत्रिकी तथा जननीति विभाग, द्रव्य विज्ञान तथा यांत्रिकी और कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय में स्थित रोबोटीक्स इंस्टीट्यूट के उत्कृष्ट प्राध्यापक है । वास्तव में इन दोनों व्यक्तियों की भारतीय अधिकारियों को डाटा नेटवर्क के विचार बेचने मे महत्वपूर्ण भूमिका रही है । वाहिनी बोर्ड के निदेशकों में दो अन्य अमेरिकियों के साथ-क्या ये भी अंकल सेम के मित्र प्रतिनिधि होंगे?

यह उल्लेखनीय है कि कोई भी स्थापित विदेशी कम्पनी इस परियोजना के साथ नहीं जुड़ी है । ऐसी अवस्था में एक ऐसी अमेरिकी विश्वविद्यालय जिसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र निश्चित रूप से संचार प्रोद्यौगिकी रही है, उसके साथ इतना संवेदनशील समझौता करने की भारत को क्या आवश्यकता थी? यहाँ हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वह यह कि आई.यू. नेट और सांख्य वाहिनी परियोजना की जमीनी सत्यता वह नहीं है जो कि बताई जा रही है? फिर यह सतह पर क्या है?

सामान्य रूप से यह दूरसंचार विभाग भारत' आई.यू.नेट. ईंक. (कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय की एक कम्पनी), इडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, (IIS) बैंगलौर, छ: अन्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी (IIT) एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी (IIT), हैदराबाद का संयुक्त प्रयास है ।

इस कम्पनी के शेयरों की भागीदारी निम्नानुसार है-

आईयूनेट इंक : 49%

दूरसंचार विभाग : 45 %

आई. आई. टी. 04 %

सूचना मंत्रालय 02%,

इस परियोजना के बचाव में सरकार के बयान और इसकी वास्तविकताओं में एक स्पष्ट विरोधाभास है ।

केबीनेट द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि अभी तक भारत के पास उच्च गति डाटा वितरण हेतु ब्रॉड बेण्डेड इन्टरनेट कनेक्टीवीटी की सुविधा नहीं है और यह हमें विदेश से लेनी होती है और यह भी कि इस तकनीक के नेटवर्किंग और रूटर के लिए हमारे पास साफ्टवेयर नहीं हैं । और इसे हम संयुक्त उपक्रम के भागीदार से प्राप्त करेंगे । किन्तु इसी प्रपत्र में आगे कहा गया है कि प्रारम्भ में दूरसंचार विभाग अपने 10,000 किमी जोड़ी फाइबर, सांख्य वाहिनी (इंडिया) लिमिटेड को 90 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करेगा । आई.यू.नेट उपकरण की खरीददारी के स्त्रोत का निर्णय करेगा । सांख्य वाहिनी (इंडिया) लिमिटेड को राष्ट्रीय और शहरी नेटवर्क तथा उसके उपकरण एवं अन्य सुविधाओं हेतु दूरसंचार विभाग अपने सभी एक्सचेंजों में स्थान एवं अन्य सुविधाएँ बिना कोई मूल्य लिए प्रदान करेगा । वास्तव मे सांख्य वाहिनी पूर्णत: दूरसंचार विभाग के रीढ़ नेटवर्क पर कार्य करेगा । सूचना तकनिकी टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।

चूँकि दूरसंचार विभाग के पास 10,000 किमी ऑप्टीकल फाइबर केबल का भारी तंत्र पहले से मौजूद है और जिसे तेजी से फैलाया जा सकता है, समय की कीमत 10,000 किमी केबल बिछाने में लगने वाले वास्तविक समय और उपलब्ध तंत्र मे ही परियोजना को चालू करने में लगने वाले समय के अंतर से डार्क फाइबर को मुक्त (फ्री) करने के समय को घटाने से प्राप्त होगी । यह अनुमान लगाया गया है कि गुणवत्ता प्रमाणित उपकरणों के प्राप्त होने के पश्चात उनकी स्थापना दूरसंचार विभाग द्वारा छ: (6) माह

के अन्दर की जा सकेगी बशर्ते फाईबर फ्री करने आदि में कोई अचानक अड़चन उपस्थित न हो ।

आईयूनेट अपेक्षा करती है कि सरकार उनके लिए सब कुछ कर दे और वे केवल स्वयं के सम्पूर्ण लाभ के लिए कम्पनी चलाएँ । प्रो. रेड्डी और प्रो. अरूणाचलम् द्वारा सरकार को दिए एक संयुक्त प्रतिवेदन मे कहा गया है कि इस कार्यक्रम का उदेश्य भारतीय विश्वविद्यालयों और अमेरिका की कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय के बीच उच्च गति डाटा नेटवर्क बनाना और उसे चलाना है । प्रस्तावित नेटवर्क राष्ट्रीय फाइबर की ऐसी रीढ़ से तैयार किया जाएगा जो केवल इस कार्यक्रम के लिए ही होगा । वर्तमान मे राष्ट्रीय नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बैंड चौड़ाई के साथ ये फाइबर मल्टीमीडिया राष्ट्रीय शैक्षणिक रीढ़ के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे । भारत की बढ़ती हुई शैक्षणिक और सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 .5- 10 GBS 85(OC-48 से OC-192) की चौड़ाई वाले बैंड और साथ ही प्रमुख भारतीय एवं अमेरिकी विश्व-विद्यालयों के सक्रिय योगदान से इंटरनेट के तीव्र विकास को गति मिलेगी । यह अंतर विश्वविद्यालयीन नेट (Inter University Net) जिसे IUNET (आईयूनेट) कहा गया राष्ट्र द्वारा सामना की जा रही शैक्षणिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डाटा तकनीकी, उपकरण और शेक्षणिक तथा सूचना संसाधनों हेतु आधुनिक डाटा नेटवर्क की उपयोगिता का प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय रीढ़ उपलब्ध कराएगा ।' इस कार्यक्रम का प्रारम्भ एवं क्रियान्वयन कार्पोरेट भागीदारों के द्वारा मिल कर किया जाए : जिसमें से एक अमेरिका मे होगा और दूसरा भारत में । ब्रॉड-बेन्ड को विषय वस्तु उपलब्ध कराने और तकनीकीयों के नियमित नवीनीकरण हेतु विश्वविद्यालयों की बड़ी भागीदारी आवश्यक है । विश्वविद्यालय विषय वस्तु के प्रकार और उच्च डाटा गति दर की माँग करती हैं, जिसे आईयूनेट पूरा करेगा । विश्वविद्यालय प्रतिभा और सामग्री की पूर्ति करेगी जो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आवश्यक है । इसी तारतम्य में दूरसंचार क्षैत्र के कार्पोरेट भागीदारों को भी शामिल करने की आवश्यकता है जो आवश्यक तकनीक उपकरण व सुविधा प्रदान कराएंगे ।कार्पोरेट भागीदार इस बात की पुष्टि के लिए भी सहायता करेंगे कि आईयूनेट केवल कार्यक्रम के उद्देश्य ही पूरे नहीं कर रहा वरन व्यापारिक दृष्टि से भी लाभदायक है । बिना आर्थिक एवं धारणीय व्यवस्था के यह कार्यक्रम सरकारी अर्थ की कमी होने पर बैठ जाएगा । हम प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम

के व्यापारिक अभिमुख होने का सुझाव देते हैं । हम एक भारतीय निगम के गठन की सलाह देते हैं, जिसमें निम्न भागीदार हों : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलाजी (IIIT) हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईस (IIS) बैंगलौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (IIT) चैन्नई, तथा मुम्बई । दूरसंचार विभाग कार्पोरेट शेयर धारक होगा । हम महसूस करते है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी विभाग के कम्पनी में भागीदार बनने के प्रस्ताव के इस भाग मे कुछ समस्याएँ हो सकती है, इसके निराकरण हेतु दूरसंचार विभाग अपने किसी व्यावसायिक उपक्रम जैसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के माध्यम से भागीदारी करके तथा विश्वविद्यालय अपने पहले से मौजूद इनके विकास हेतु व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से भागीदारी कर सकते है? दूरसंचार विभाग की भागीदारी इस कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु अत्यन्त आवश्यक है । केवल दूरसंचार विभाग द्वारा अपने केप्टवि फाइबर को लीज पर अथवा इक्वीटी के रूप में देने से ही क्या इस वर्ष में नेटवर्क स्थापित करना सम्भव हो सकेगा । अमेरिकी कम्पनी में भागीदार होंगे कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय तथा अमेरिका की एक बहुत बड़ी दूरसंचार कम्पनी । तथा ये इस कार्यक्रम के लिए ऑप्टीकल, नेटवर्कीग, सोफ्टवेयर और आधुनिक प्रयोग तकनीक उपलब्ध कराऐंगे । दोनो निगम आईयूनेट कार्यक्रम चलाने के लिए आईयूनेट कंर्सोटीयम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर करेगे ।

यह दोनों कार्पोरेशन (निगम) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए इक्वीटी एवं ऋण के माध्यम से आवश्यक पूंजी जुटाएंगे । इनके सम्बन्ध मे विस्तृत प्रावधान कम्पनी निर्माण प्रक्रिया के समय मे किए जा सकेंगे ।

आगे ध्यान से पढ़ें । यह भाग स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 का उलंघन है।

कार्यक्रम :-

प्रारम्भ में प्रमुख शहरों मे 8-10 नोड के साथ एक नेटवर्क टोपोलॉजी स्थापित की जाएगी। उपयोगकर्ताओं तथा राष्ट्रीय रीढ़ में उपलब्ध तंत्र और यातायात पूर्वानुमान के अध्ययन के पश्चात् ही इस जाल की सही रूपरेखा और यांत्रिकी नीति निर्धारित की जाएगी । विश्वस्तरीय उच्च बैंड चौड़ाई वाले अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव हेतु दो या अधिक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे इस कार्यक्रम को उपलब्ध कराने की हमारी योजना है । प्रारम्भ में

नेटवर्क- में उच्च बैंड चोड़ाई वाले उपस्थिति (Point of Presence) 25 होंगे, जिन्हें 100 तक बढ़ाया जा सकेगा ।

इस प्रकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य डाटा यातायात के द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभप्रद डाटा सेवा उपलब्ध कराना सम्भव होगा । स्वतन्त्र सेवा देने वालों को भी बैंड चौड़ाई उपलब्ध कराने की योजना है, जो मल्टीमीडिया विषय वस्तु वाले व्यावसायिक ग्राहकों तथा व्यक्तियो को सेवा बेच सकेंगे । व्यक्तिगत तथा संस्थागत उपयोगकर्ताओं, कीमतों एवं सेवाओं के प्रबन्धकों को यह अपने विभिन्न सिद्धांतों तथा तकनीकों जिसमें उच्च बैंड चौड़ाई वाले संचार की आवश्यकता होती है, को सिद्ध करने हेतु परिक्षण स्थल उपलब्ध कराने की शुरूआत होगी । इससे उच्च कोटि विभेदीकृत सेवाएँ प्रदान करने तथा उपयोगकर्ताओं को अपनी लागतें एवं सेवाएँ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी । अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के अनावश्यक बहुतायत में उपयोग को रोकने के लिए भारत के सभी नोड पर दर्पण साइट लगाने की हमारी योजना है जो अनुरोधों को पकड़ने में सहायता करेगा । इसी प्रकार की दर्पण साइट अमेरिका में भी उपलब्ध होगी जो अमेरिका मे भारतीय सूचनाओं की आवश्यकता को पूरा करेगी ।

प्रारम्भिक साइट्स का चयन उपलब्ध माँग के आधार पर किया जाएगा । आईयूनेट उपस्थिति बिन्दू बनाने से पहले कॉलेजों विश्वविद्यालयों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सेवा देयकों के साथ समझौते करेगा । ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की इस स्थान पर उपलब्धता तथा फाइबर ऑप्टिक टर्मीनल और रूटर पर निवेश करने की उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर अन्य स्थानों पर सेवाओं का विस्तार किया जाएगा । हमें आशा है कि शैक्षणिक सेवाओं की गुणवत्ता, औचित्य और उनका एकत्रीकरण जो कि भागीदार शैक्षणिक संस्थाएँ आईयूनेट को देने जा रही हैं को देखते हुए, आईयूनेट मे दाखिल होने हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एक प्रारम्भिक सहयोग देने की सरकार की मंशा होनी चाहिए । इन्टरनेट 2 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ऐसा ही सहयोग अमेरिका ने सरकारी वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध करवाया था ।

कीमत और समय अनुमान

प्रारम्भ में भारत के 6 से 10 प्रमुख शहरों की नेटवर्किंग से चालू करने में बुद्धिमानी होगी और इसमें लगभग 10,000 रूट मील लगेंगे । घरेलू बैण्ड चौड़ाई की कीमत दूरसंचार

विभाग के साथ होने वाली आपसी बातचीत में शामिल की जाएगी । भूमंडलीय जुड़ाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय लिंक की कीमत भी तय करनी होगी । नेटवर्क की स्थापना के पश्चात शैक्षणिक, पुस्तकालय और प्रशिक्षण कार्यक्रमो की कीमत पर आपसी बातचीत होगी । यदि अंतर्राष्ट्रीय लिंक की कीमत लगभग 10 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगी तो कुल परियोजना किमत 36 मिलियन डॉलर तक आकी जा सकती है । अंतर्राष्ट्रीय बैंड चौड़ाई शुल्क आवर्ती होता है ।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आईयूनेट की स्थापना दूरसंचार विभाग के उपलव्यब्ध नेटवर्क तथा वर्तमान डार्क फाईबर को लाईट करके जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए । इसी के साथ आईयूनेट शैक्षणिक साफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा जो विद्यार्थियों को किसी भी स्थान पर किसी भी समय उनकी जरूरतो के अनुसार शिक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा साथ ही इसमें विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार शैक्षणिक पद्धति चुनने और तद्नुसार समायोजित करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी । सार्वभौमिक पुस्तकालय सुविधाओं, संयुक्त तथा भागीदारी वाले कार्यक्रमों में बेन्ड चौड़ाई में साझेदारी तथा मूल परिवर्तन जैसे दूर-संवेदना तथा आभासी तकनीकियाँ उपलब्ध सेवाओं को और सुदृढ़ बनाएगी । हम मानते है कि पहुँच, बैंड चोड़ाई और विषय-वस्तु इस बात का निर्धारण करेंगे कि भारत में आईयूनेट कितनी तेजी से प्रगति करता है ।

दूरसंचार विभाग की भागीदारी, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग और एक बड़े दूरसंचार निगम के साथ 9 माह के भीतर एक राष्ट्रीय रीढ़ की स्थापना सम्भव है । और जैसा हम अनुमान लगाते हैं कि 18 महिनों में आईयूनेट एक वास्तविकता हो जाएगा ।

हमने बिन्दु रेखाओं पर हस्ताक्षर किए हैं ।

प्रो. रेड्डी और अरुणाचल! के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि वे हमेशा की तरह भारत को एक दुधारू गाय की तरह देख रहे है । वे अमेरिकन निगमों के लिए पुन: एक बड़ा दूरसंचार तकनीक बाजार ढूंढ रहे हैं या इसमें और भी कुछ है? आखिर अमेरिकी निगम जिनका सुझाव रेड्डी और अरूणाचलम दे रहे हैं स्वयं सामने क्यों नहीं आ रहे? यदि भारतीय भागीदार को भूमि, एक्सचेंज में स्थान, प्रारम्भिक बैड़ चोड़ाई, पैसा और साथ

ही बिक्री प्रवर्धन देना है तो फिर भारत द्वारा एक विदेशी व्यक्ति को नियंत्रित करने, आदेश देने और लाभ को बाहर ले जाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि यह तकनीक कहीं ओर उपलब्ध नहीं है । दूरसंचार विभाग अपनी शर्तो पर बहुत आसानी से यह तकनीक खरीद सकता है और वह भी बिना इस तरह के पचड़े में पड़े ।

प्रमुख प्रश्न जो जनता पूछना चाहेगी:

(1) राजग के घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए नहीं खोला जाएगा तो क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है?

(2) स्वदेशी पर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एजेंडा में यह वादा किया गया है कि दूरसंचार विभाग और विसनिलि को विदेशों में परियोजनाएँ लेकर विश्वस्तरीय बनाया जाएगा ।

(3) क्या यह भारतीय दूरसंचार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है? सरकार ने कहा था कि दूरसंचार अधिनियम को आधुनिक बनाने के लिए इसमें संशोधन किए जाएंगे । लेकिन कहीं भी रीढ़ नेटवर्क या गेटवे को एक विदेशी कम्पनी के लिए खोलने की मंशा का प्रदर्शन नहीं था । और अभी तो संशोधनों को संसद की अनुमति मिलना शेष है ।

(4) क्या इसके बाद भारत की पूरी दूरसंचार प्रणाली एक विदेशी संस्था के हाथ का खिलौना नहीं बन जायेगी?

(5) सांख्य वाहिनी बोर्ड के संविधान के अनुसार आईयूनेट और दूरसंचार विभाग दोनों के तीन सदस्य होगें और दूसरे छोटे भागीदारों में से प्रत्येक का एक-एक सदस्य नामांकित होगा । शुरू के पांच सालों के लिए मुख्य प्रबंधन अधिकारी (CMD) आईयूनेट का होगा। सभी एक्सजेंजों मे सांख्य वाहिनी (ईं.) लिमिटेड का एक स्थान होगा और कम्पनी दूरसंचार विभाग की भूमि पर चलेगी । इसका अर्थ यह हुआ कि दूरसंचार विभाग के नेटवर्क का एक विदेशी कम्पनी द्वारा मुक्त और असीमित- उपयोग ।

दूरसंचार विभाग ने अन्य भागीदारों के बारे में जांच पड़ताल क्यों नहीं की?

(6) डा. अरूणाचलम् और प्रो. रेड्डी ने जो कुछ भी कहा उसको पूरी तरह मान लेने के बारे में अभी तक सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । किसी भी सरकारी सौदे में एक से अधिक स्त्रोत की भागीदारी की पड़ताल करने की परम्परा है । इसको नजरअंदाज करना बछडे के प्रति प्रेम दर्शाता है ।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह सबसे अच्छा सम्भव समझौता है । यदि अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया में समय अधिक लग रहा था तो सरकार ने अधिक अनुभव वाली स्थापित कम्पनी से सम्पर्क क्यों नहीं साधा?

क्या आईयूनेट की 49% की भागीदारी जायज है? उनके सभी वादे अनिश्चित हैं और वे मुख्य रूप से सोफ्टवेयर से संबन्धित हैं । इस बात की भी सम्भावना है कि शुल्क मुक्ति की छूट का दुरूपयोग राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में किया जाएगा ।

(7) आखिर आईयूनेट को पहले पाँच साल के लिए कम्पनी के प्रथम मुख्य प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति का मौका क्यों दिया गया? (8) इस बात की क्या गारन्टी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामांकित आईयूनेट के तीन सदस्य सीआईए के एजेंट नहीं होंगे?

(9) दूरसंचार विभाग के संसाधनों का उपयोग करने की जिस तरह की छूट सांख्य वाहिनी को दी जा रही है उसमें इस बात की क्या गारन्टी है कि हमारी व्यापार और सामरिक गुप्त सूचनाओं की जासूसी नहीं होगी? (इसके सम्बन्ध में विस्तार से आगे)

कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह अमेरिका की विश्व चौधराहट के इरादों की रणनीति का ही एक भाग सिद्ध होगी । यह संदेह करने का प्रर्याप्त कारण है कि इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का सीधा हाथ है ।

(10) सरकार कहती है कि भारत की संस्कृति और शिक्षा की रक्षा की जाएगी । यह उनका बहाना है जो उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी पूंजी निवेश को शिक्षा मे न आने देने के लिए बनाया था । लेकिन क्या सांख्य वाहिनी के माध्यम से भारतीय शिक्षण संस्थान सीधे अमेरिकी संस्थानों से नहीं जुड़ जाएंगे तथा भारतीय प्रतिभाओं के हरण के लिए सीधा आधार उपलब्ध होगा?

(11) क्या यह पूरे शिक्षातंत्र और पाठ्यक्रम को गड़बड़ नहीं कर देगा । विशेष रूप से जब सरकार भारतीय विद्यार्थियों को दुनिया की सभ्यता में भारत की भूमिका पढ़ाने पर अत्यंत जोर दे रही है? अमेरिका हमेशा दुनिया पर अपना तंत्र, अपनी सभ्यता, अपना संगीत और खान-पान की आदतें थोपना चाहता है । उनका शिक्षा तंत्र केवल इसका एक माध्यम बनेगा । क्या भारतीय उच्चाधिकारी इसकी अनुमति देने में अत्यधिक उदारता नहीं बरत रहे हैं?

(12) क्या यह प्रतिभा पलायन को बढ़ावा नहीं देगा?

(13) इस पूरे प्रकरण को इतना गुप्त क्यों रखा गया? शासन से कम से कम पारदर्शिता की अपेक्षा तो की जाना चाहिए ।

आईआईटी और वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति की जासूसी की संभावना भी एक सम्भावित खतरा है ।

राजा से अधिक देश भक्त

एक शासकीय नोट के अनुसार कारनेगी मेलोन विश्वविद्यालय दूरसंचार विभाग को यह विश्वस्तरीय तकनीक बिना हस्तांतरण शुल्क के देना चाह रही थी । किन्तु सरकार ने इसे एक संयुक्त उपक्रम के रूप में लेना उचित समझा । क्यों? इस प्रश्न पर कि यह एक सरकारी कम्पनी के साथ क्यों नहीं किया गया उसी नोट में कहा गया है कि आईयूनेट को यह तकनीक एक सरकारी कम्पनी को हस्तांतरण करने में असुविधा होती । निश्चित रूप से दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ।

राष्ट्रीय तकनीकी ओर व्यापारिक विकास में सहयोगी होने वाले बहुत उच्च बेन्ड चौड़ाई वाले मल्टीमीडिया प्रयोग राष्ट्रीय नेटवर्क का भारत में विकास न हो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन केवल इसीलिए हमें आईयूनेट में जाने की आवश्यकता नहीं है। 'साख्य वाहिनी' कार्यक्रम के लिए हमें दूरसंचार विभाग के वर्तमान नेटवर्क में से कुछ फाइबर राष्ट्रीय इन्टरनेट रीढ़ बनाने के लिए विशेष रूप से मुक्त (फ्री) कर रहा हैं । यह 10 जीबीएस या इसके अधिक चौड़ाई वाले फाईबर को बढ़ावा देगा, ऐसी आशा है । दूरसंचार तकनीक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत, अमेरिका सहित अन्य तकनीक समृद्ध देशों के समकक्ष खड़ा हो सकेगा । भारत अपने सौंफ वेयर बना

लेने में पूरी तरह सक्षम है । हम अपने ज्ञान के आधार पर सूचना तकनीक के सुपर पॉवर बनने की क्षमता रखते हैं । इसलिए आईयूनेट के लिए यह हड़बड़ी अर्थहीन है ।

इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग और आईयूनेट के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (MOU) मे कहा गया है कि प्रारम्भ मे इस उच्च गति डाटा नेटवर्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव विसनिलि से लीज पर होगी । किन्तु सहमति पत्र, सरकार से अनुमति लेने के पश्चात अन्य बैंड चौड़ाई प्रदायकर्ता संगठनों से बातचीत करने की छूट देता है, वर्तमान मे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव पूर्णत विसनिलि का अधिकार क्षेत्र है ।

संचार एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है । इन्टरनेट और सेटेलाईट संचार के इस युग में भी प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक एवं व्यावसायिक स्वार्थ और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर लगातार नजर रखता है । यह चिताएँ आइयूनेट- दूरसंचार विभाग के बीच के इस समझौते को शंकास्पद और खतरनाक बनाती हैं ।

आज अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक जासूसी नेटवर्क यूरोप मे एक गर्म मुद्दा

दिसम्बर 1997 में आई एक यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि अमेरिका ने एक ऐसा विस्तृत नेटवर्क फैला लिया है कि वह प्रत्येक यूरोपियन नागरिक की जासूसी कर सकता है । यह अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जासूसी नेटवर्क पूरे विश्व के प्रत्येक टेलीफोन, ई-मेल और टेलेक्स संचार को पकड़ सकता है । एकेलीन (ECHELON) नामक यह अमेरिकी तंत्र यूरोप में एक गम्भीर मुद्दा बन गया है । क्योंकि यह सुनिश्चित हो गया है कि ब्रिटेन के न्यूर्याक मूर्स की नैनविल हिल्स पर अमेरिकी नियंत्रण में बने कूटनीतिक केन्द्र में इसकी स्थापना हुयी । 1996 में यूरोपियन संसद की नागरिक स्वाधीनता समिति द्वारा इस नेटवर्क की सच्चाई मालूम करने के लिए कई एजेंसियां बनायी गई हैं । इस नेटवर्क जिसके बारे में अमेरिका ने कभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की अब इसकी पुष्टि हो चुकी है । 13 फरवरी 2000 को वाशिंगटन पोस्ट ओर संडे टेलीग्राफ में एक साथ छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका अन्य यूरोपीय देशों में एंग्लोफोन जासूसी नेटवर्क के माध्यम से अभूतपूर्व कानूनी और राजनैतिक खतरों का सामना कर रहे हैं ।

हाल ही मे बाहर आए एक अमेरिकी परिपत्र मे पिछले हफ्ते यह स्वीकारोक्ति की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय छिप कर संचार पकड़ने वाला तंत्र कार्य कर रहा है । एकेलान जासूसी तंत्र जो पाँच अंग्रेजी भाषी देशों द्वारा चलाया जाता है । किन्तु इसका नियंत्रण अमेरिका के हाथों में है । ऐसी सूचना है कि यह सेटेलाईट से पूरे विश्व में कहीं भी प्रसारित होने वाले टेलीफोन, फेक्स और ई-मेल को नियंत्रित कर सकता है ।

अमेरिकी जासूसी प्रमुखों द्वारा एकेलीन का दुरुपयोग व्यक्तियों की जासूसी करने और व्यवसायिक गोपनीयताएं अमेरिका के व्यापारियों को उपलब्ध कराने में किया जा रहा है ।

एकेलान इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के बारे में यूरोपीय संसद की नई जाँच से कुछ और मुद्दे सामने आएंगे जब यूरोपीय संसद के सदस्य उस जांच की रिपोर्ट पर मार्च में संसद मे बहस करेंगे । उस परिपत्र में ऐसे अनेक सौदों की सूची है जिनमें अमेरिकी कम्पनियों ने एन. एस. ए. द्वारा की गई जासूसी के आधार पर उन सौदों को प्राप्त कर लिया जो अन्यथा यूरोपीय फर्मों को मिलते । इन कार्यवाहियों के कारण तथा कथित हानि उठाने वाली कम्पनियों में फ्रांस की एयर बस कंसोर्टीयम और थॉमसन सी एस एफ शामिल है । पूर्व एनएसए एजेंट बायने मंडसन ने पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलियन टीवी पर बताया कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका ने अपने आधारों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित कर एशिया के इंडोनेशिया में हो रहे महत्वपूर्ण व्यापार समझौते में अपनी कम्पनी ए टी एण्ड टी के लिए आधा भाग लिया था जो पूर्व में जापान की एनआरसी को जाने वाला था ।

फ्रांस में अमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध एक याचिका दायर होने वाली है । इटली में न्यायिक और संसदीय जाँच चल रही है, और जर्मनी के सांसदों ने एक जाँच की मांग की है ।

अमेरिका में इस वर्ष अमेरिकन काँग्रेस द्वारा एकेलान तंत्र के कारण संभावित व्यक्ति स्वतंत्रता के खतरे पर जाँच प्रारम्भ की जाएगी ।

विशेषज्ञ याद दिलाते है कि अस्सी के दशक में अमेरिका ने किस प्रकार श्रीलंका मे एक सेटेलाइट संचार तंत्र बनाने का प्रयास किया था जिसे भारत के भारी विरोध के कारण

जयवर्धन सरकार ने अनुमति नहीं दी थी । यदि सांख्य वाहिनी के स्थापना की अनुमति दे दी जाती है तो अमेरिका को कहीं ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अमेरिकी आईयूनेट को भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीधे हस्तक्षेप करने की जो सुविधा दी जा रही है, उसका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो विरोध हो रहा है, उसका आधार यही है । नई दूरसंचार नीति मे वादा किया गया है "भारत के प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा हितों की रक्षा की जाएगी ।" जैसा पहले बताया गया है कि प्रस्ताव मे सरकार को यह सलाह दी गयी है कि वह विश्वविद्यालयों को नेटवर्क मे शामिल होने के लिए प्रारम्भिक समय में कुछ सहयोग करे । इससे ऐसा प्रतित होता है कि सरकार आईयूनेट को एक ऐसे निवेश के लिए दोहरी जमानत दे रही है जो आईयूनेट ने किया ही नहीं ।

यह आश्चर्यजनक है कि परियोजना के प्रस्ताव में या अन्यत्र कहीं भी सरकार द्वारा सुरक्षा और बौद्धिक सम्पदा अधिकार को सांख्य वाहिनी द्वारा संभावित नुकसान की कोई चर्चा नहीं की गयी है । जहां एक ओर अमेरिकन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारियां उनके स्रोत पर ही परखी जाएंगीं इस तरह की कोई व्यवस्था भारत में होने के कोई संकेत नहीं दिए गए है । वास्तव में परियोजना प्रस्तावक और सरकार इसे सूचनाओं का अमेरिका से भारत की ओर एक तरफा यातायात मान कर चल रहे हैं । भारतीय विश्वविद्यालयों विशेषकर आईआईटी और आईआइआईटी जैसी नोडल एजेंसियों में हो रहे महत्वपूर्ण अध्ययन कार्यो का अनदेखा कर दिया गया है ।

यह एक ऐसा उपक्रम है जिसे तत्काल पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए । इस अवस्था में सांख्य वाहिनी को निरस्त करने से कोई हानि नहीं होगी । यह स्थान उन मजबूरियों ओर परिस्थितियों को बताने का नहीं है जिनके चलते दूरसंचार विभाग ने यह समझौता किया । कोई भी सही सोच वाला भारतीय इसे बिना चुनौती दिए नहीं होने देना चाहेगा ।

प्रकाशक

अर्चना प्रकाशन

१७, दीनदयाल परिसर,

ई- २, महावीर नगर, भोपाल-४६२०१६ दूरभाष : ५६६६८६५

पुष्प : पच्चासीवां

संस्करण :

प्रथम संस्करण, वर्ष प्रतिपदा २०५७ युगाब्द ५१०२ (०५-०४-२०००)

प्रस्तुति :

स्वदेशी जागरण मंच, भोपाल

मूल्य : पाँच रुपये

अक्षर -संयोजन :

प्रोम्प्ट कम्प्यूटर एजूकेशन

मुद्रक : विश्वास ऑफसेट प्रिंटिंग, भोपाल